

My Notes.....

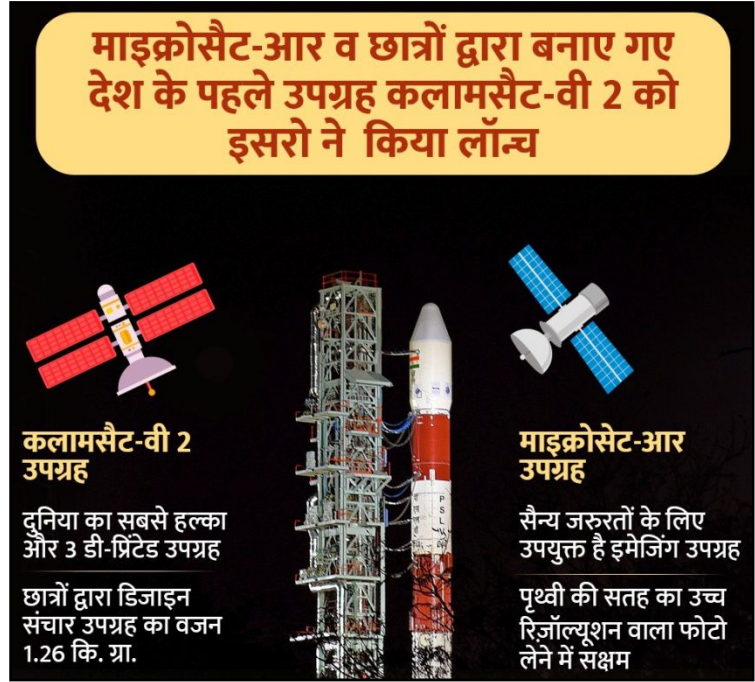
राष्ट्रीय

इसरो ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह

इसरो ने 24 जनवरी 2019 को दुनिया के सबसे छोटा सैटेलाइट कलामसैट वी-2 को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। कलामसैट सैटेलाइट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। खास बात यह कि इस उपग्रह को भारतीय छात्रों के एक समूह ने तैयार किया है। कलामसैट वी-2 को पीएसएलवी-सी 44 मिशन के तहत किया गया।

क्या है

1. इससे पहले आजतक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब सिर्फ 1.2 किलोग्राम का कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया हो। लेकिन इसरो और भारतीय छात्रों ने यह कारनामा कर दिखाया है।
2. इसरो ने इस सैटेलाइट के बारे में बताया है कि इस उपग्रह से शौकिया तौर पर रेडियो सेवा चलाने वालों को अपने कार्यक्रमों के लिए तरंगों के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। इसरो ने बताया कि इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वैज्ञानिक और भविष्य के इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करेगा। कलामसैट को चेन्नई स्थित स्पेस एजुकेशन फर्म स्पेस किड्स इंडिया नाम की स्टार्ट-अप कंपनी ने बनाया है।
3. कलामसैट सैटेलाइट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। इसे चेन्नई के छात्रों के समूह स्पेस किड्स ने तैयार किया है।
4. इन छात्रों को स्पेस किड्स नाम इसरो के चेयरमैन डॉ. के सिवन ने दिया है। यह पीएसएलवी के नए संस्करण पीएसएलवी-डीएल का पहला सैटेलाइट है।



ये है कलामसैट सैटेलाइट की खासियत

1. कलामसैट सैटेलाइट को हैम रेडियो ट्रांसमिशन (शौकिया रेडियो ट्रांसमिशन) के कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल, हैम रेडियो ट्रांसमिशन से मतलब वायरलैस कम्युनिकेशन के उस रूप से है जिसका इस्तेमाल पेशेवर गतिविधियों में नहीं किया जाता है।
2. यह पहला मौका नहीं है, जब कोई बेहद हल्का सैटेलाइट लॉन्च किया है। पिछले साल एक अन्य भारतीय छात्र ने ही इससे भी हल्के उपग्रह को बनाया था, जिसका वजन मात्र 64 ग्राम था।

3. इस उपग्रह को नासा ने चार घंटे के मिशन पर सब-ऑर्बिटल फ्लाइट पर भेजा था। लेकिन बता दें कि सब-ऑर्बिटल फ्लाइट के दौरान उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचते हैं लेकिन पृथ्वी की कक्षा में नहीं जाते हैं।

सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट मंजूर

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। गृहमंत्रालय ने कार्यबल का गठन इसलिए किया था, ताकि सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्षेत्रों की निशानदेही की जा सके। कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) ने किया और उसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बलों, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

क्या है

- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसे पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा।
- इसके लिए इसरो और रक्षा मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग किया जाएगा। सीमा प्रहरी बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं।
- लघु कालीन आवश्यकताओं के तहत सीमा प्रहरी बलों के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिए बैंडविथ का प्रबंध किया जाएगा।
- मध्यम अवधि की आवश्यकता के मद्देनजर इसरो एक उपग्रह लांच कर रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा।
- दीर्घकालीन अवधि के तहत गृह मंत्रालय नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा ताकि अन्य एजेंसियां उपग्रह संसाधनों को साझा कर सकें।
- दूरदराज के इलाकों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपग्रह संचार की सुविधा दी जाएगी।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है-

1. द्वीप विकास
2. सीमा सुरक्षा
3. संचार और नौवहन
4. जीआईएस और संचालन आयोजना प्रणाली
5. सीमा संरचना विकास

SC/ST के संसोधित कानून पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी (SC/ST) के संसोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में रोक नहीं लगाई जा सकती। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहले का फैसला जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित ने दिया था। अब जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पीठ का गठन करना है। लिहाजा इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना है।

क्या है

- सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि इन जनहित याचिकाओं को पुनर्विचार याचिका के साथ सुना जाए या इसकी सुनवाई अलग से हो।
- बता दें कि इस संशोधन कानून को लेकर दोबारा सुनवाई के लिए वकील पृथ्वीराज चौहान और प्रिया शर्मा ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दायर याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है।

3. ध्यान हो कि अनुसूचितजाति और अनुसूचितजनजाति संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

संसद में विधेयक लाकर पलटा गया था SC का फैसला

1. बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के जरिये एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामले में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
2. न्यायालय के इस फैसले को समाज के एक हिस्से ने कानून के प्रावधानों को हल्का किये जाने के तौर पर देखा। इसको लेकर एससी-एसटी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली थीं।
3. सरकार ने समुदाय की चिंताओं का निराकरण करने के लिये संसद के मॉनसून सत्र में एससी-एसटी कानून में संशोधन के लिये एक विधेयक को पारित कराकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया।

सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा

सरकार ने सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाएगी। किसी भी आपदा के बाद विभिन्न व्यक्ति और कई संगठन प्रभावित लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए कार्य करते हैं। मानवता के प्रति उनका यह योगदान और उनके द्वारा की गई सेवा को अक्सर मान्यता नहीं मिलती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार के गठन की सलाह दी है ताकि ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को पहचान दी जा सके। सभी भारतीय नागरिक और संगठन जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों यथा रोकथाम, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, शोध या पूर्व चेतावनी में विशिष्ट योगदान दिया है, वे सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के योग्य हैं। 2019 के लिए इस पुरस्कार का प्रचार-प्रसार किया गया था और 19 दिसंबर, 2018 से 7 जनवरी, 2019 तक नामांकन आमंत्रित किए गए थे। 300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं।

क्या है

1. वर्ष 2019 के लिए गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की आठवीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चन्द्र बोस आपदा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 51 लाख रुपये की नगद धनराशि तथा एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
2. एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का गठन 2006 में किया गया और यह विशेषज्ञ बचाव और अनुक्रिया बल है और इसका दायित्व क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा है।
3. बटालियन ने 314 प्रमुख कारवाइयों में भाग लिया है और 50,000 से अधिक लोगों को बचाया है। हाल के केरल की बाढ़ में बटालियन ने 5338 पीड़ितों को बचाया और 24000 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
4. एनडीआरएफ की यह बटालियन लेह में बादल फटने की घटना (2011), केदारनाथ बाढ़ (2013), चक्रवाती तूफान (2014), चेन्नई बाढ़ (2015) तथा त्रिपुरा बाढ़ (2018) जैसी आपदाओं में भागीदारी की है। बटालियन ने 2010 में दिल्ली के मायापुरी विकिरण की घटना के दौरान खतरों को समाप्त करने में कारगर भूमिका निभाई थी।
5. बटालियन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय आपदा प्रबंधन कार्य किए हैं। 2015 में नेपाल भूकम्प के बाद सबसे पहले काठमांडू पहुंचने वाले दलों में बटालियन की छः टीमों थीं। उनकी टीमों को जापान की फूकुसीमा डाइची परमाणु आपदा (2011) और इंडोनेशिया में हाल की सुनामी (2018) में भी भेजा गया था।
6. अनुक्रिया और राहत कार्य के अतिरिक्त एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने एसडीआरएफ, एनसीसी, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा नेपाल पुलिस को प्रशिक्षित किया है। बटालियन द्वारा चलाये गये समुदाय आधारित क्षमता सृजन कार्यक्रमों से 9 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

प्रवासी भारतीय दिवस 2019

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी, 2019 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश), में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किए। पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। अधिकांश प्रवासी भारतीयों की कुंभ मेले और गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होने की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के बाद प्रतिभागी 24 जनवरी को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की यात्रा करेंगे। 25 जनवरी को प्रवासी जन दिल्ली के लिए प्रस्था न करेंगे और 26 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। नॉर्वे के सांसद श्री हिमांशु गुलाठी विशिष्ट अतिथि और न्यूजीलैंड के सांसद श्री कंवलजीत सिंह बक्शी सम्मानित अतिथि होंगे।

इस संस्करण के मुख्यम आयोजन इस प्रकार हैं-

1. 21 जनवरी, 2019- युवा प्रवासी भारतीय दिवस। यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीयों को नये भारत के साथ जुड़ने के अवसर उपलब्ध करायेगा।
2. 22 जनवरी, 2019- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ की उपस्थिति में उद्घाटन।
3. 23 जनवरी, 2019 - समापन सत्र और राष्ट्रमपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार प्रदान करना।
4. इस आयोजन के दौरान विभिन्न 9 परिपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

प्रवासी भारतीय दिवस

1. पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
2. पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्माद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
3. अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर दो साल में एक बार किया जाता है। यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है।
4. सम्मेलन के दौरान भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चुने गये भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किये जाते हैं।
5. 14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी, 2017 को बैंगलूरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।
6. 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था- प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुर्नभाषित करना। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा था कि प्रवासी भारतीय भारत की श्रेष्ठतम संस्कृति, लोकाचार और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने योगदानों के लिए सम्मानित हैं। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता के मुख्य क्षेत्र के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ लगातार संबंधों के महत्वी पर जोर दिया था।

नौसेना का सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास शुरू

मुंबई हमले के दस साल बाद नौसेना का सबसे बड़ा दो दिवसीय रक्षा अभ्यास 22 जनवरी 2018 से शुरू हुआ। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह समुद्र तट से सटे सभी 13 राज्यों की 7,516 किमी लंबी सीमा पर चलाया जा रहा है। मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले समुदाय भी इसका हिस्सा बने हैं।

क्या है

1. इस युद्धाभ्यास में नौसेना और तटरक्षक बल ने अकेले 139 पानी के जहाजों की तैनाती की है। वहीं 35 एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर्स, हेलिकॉप्टर्स, ड्रोन, पेट्रोल बोट्स, कोस्टल पुलिस फोर्स और सीआईएसएफ के जवान इसमें शामिल हैं। इसका कोडनेम सी विजिल 2019 है।
2. नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने बताया कि सी विजिल मुख्यतः इस बात की जांच करेगा कि 26/11 के बाद तटों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम आखिर कितने कारगर साबित हुए हैं।
3. सी विजिल के साथ ऑपरेशनल, टेक्निकल और प्रशासनिक ऑडिट भी किया जाएगा, जो हमारी ताकत और कमजोरी के बारे में सही जानकारी देगा।
4. 26/11 हमले के बाद जांच में सामने आया था कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने से उस हमले के बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी। उस समय भी इस तरह की जानकारी मिली थी कि आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में घुस सकते हैं।

आईएफटीएक्स-2019

भारतीय अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (आईएफटीएक्स)-2019 की तैयारियों से संबंधित कार्यरूप को अंतिम रूप देने के लिए 23-24 जनवरी 2019 को पुणे में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मिस्र, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजर और जाम्बिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

क्या है

1. भारतीय अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (आईएफटीएक्स)-2019 18 से 27 मार्च 2019 तक पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में होने जा रहा है।
2. यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों के साथ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाने और संयुक्त शांति अभियानों को गति देना है।
3. इस अभ्यास से संबंधित प्रारंभिक योजना दिसंबर 2018 में आयोजित सम्मेलन में ही तैयार कर लिया गया था।
4. आईएफटीएक्स-2019 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य राष्ट्रों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इससे इन देशों के साथ पहले से ही मजबूत रणनीतिक सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

आईएनएस कोहासा

एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, चौयरमैन सीओएससी और नौसेना प्रमुख ने नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस शिबपुर की आईएनएस कुहासा के रूप में शुरूआत की। इस भव्य समारोह में वाइस एडमिरल विमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी कमांडर-इन-चार्ज, अंडमान-निकोबार कमान सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह कार्यक्रम में औपचारिक गॉर्ड प्रस्तुति कमीशनिंग छोटी पताका फहराना और कमांडिंग अधिकारी, कमांडर कुलदीप त्रिपाठी द्वारा जहाज का वारंट पढ़ना शामिल थे। आईएन कुहासा को यह नाम व्हाइट बेलिड सी ईगल के नाम पर दिया गया है जो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का स्थानीय बड़ा शिकारी पक्षी है।

क्या है

1. एनएस शिबपुर को उत्तरी अंडमान में निगरानी बढ़ाने के लिए एक फारवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस (एफओएबी) के रूप में वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था।
2. कोको आइलैंड दूसरा नाम म्यांमार के नजदीक स्थित होने और भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन ईईजेड के व्यापक विस्तार के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन जाता है। एयरफील्ड भारतीय वायु सेना और तटरक्षक विमानों के लिए विलगन परिचालन उपलब्ध कराता है।

3. यह वायु स्टेशन शॉर्ट रेंज मेरीटाइम टोही (एसआरएमआर) वायुयान और हेलीकॉप्टर संचालित करता है। यह वायुयान स्टेशन दायित्व के एनसी क्षेत्र में ईईजेड निगरानी एन्टी पोचिंग मिशन खोज और बचाव (एसएआर) और मानवीय सहायता आपदा राहत एचएडीआर मिशन संचालित करता है।
4. मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट 370 के खोज परिचालनों के दौरान नौसेना और तटरक्षक के डार्नियर डीओ 228 इसी बेस से परिचालित हुए थे।
5. नीति आयोग ने एनएस शिबपुर की समावेशी द्वीप विकास के एक हिस्से के रूप में एक 'अर्ली बर्ड' के रूप में पहचान की थी।
6. इस दिशा में एनएस शिबपुर नागरिक उड़ान परिचालन में सहायता प्रदान करने के लिए यह सभी तरह से तैयार है। इसका रन-वे बढ़ाकर दस हजार फुट करने की भी योजना है ताकि निकट भविष्य में यह बड़ी बॉडी के वायुयानों का परिचालन भी कर सके।

रक्षा मंत्रालय ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी

रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसले में 31 जनवरी 2019 को भारतीय नौसेना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से 6 पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को मंजूरी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद (DAC) की बैठक में किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डीएसी ने थलसेना के लिए करीब पांच हजार मिलान टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी।

क्या है

1. अधिकारियों ने कहा कि परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी, जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लैटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है।
2. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी। नए मॉडल के तहत लागू होने के लिए सरकार की मंजूरी वाली पहली परियोजना 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से नौसेना के लिए 111 हेलिकॉप्टर की खरीद की थी।

अन्तरराष्ट्रीय

सातवें आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री के.जे. अल्फोंस ने वियतनाम के हा लोंग शहर में आसियान देशों तथा भारत के पर्यटन मंत्रियों की सातवीं बैठक में शामिल हुए। श्री के.जे. अल्फोंस ने वियतनाम के संस्कृति, खेल तथा पर्यटन मंत्री श्री एनगुयेन एनगोक थियेन के साथ पर्यटन मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की। पर्यटन मंत्रियों ने 2018 में आसियान तथा भारत के पर्यटन प्रदर्शन पर विचार किया। 2018 में आसियान तथा भारत में 139.5 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

क्या है

1. बैठक के दौरान सिंगापुर में 15 नवम्बर 2018 को आसियान-भारत अनौपचारिक ब्रेक फास्ट सम्मेलन के निर्णयों का स्वागत किया। पर्यटन मंत्रियों ने आसियान-भारत पर्यटन सहयोग वर्ष 2019 लांच किया और आशा व्यक्त की कि दोतरफा पर्यटन आगमन की दृष्टि से सहयोग बढ़ेगा और आसियान तथा भारत के बीच लोगों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. इससे पहले, 2018 में आसियान-भारत स्मृति सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किया था।

3. इस विषय पर थाईलैंड में 20वें आसियान-भारत पर्यटन कार्य समूह की बैठक में विचार किया गया था और आसियान-भारत पर्यटन वर्ष की गतिविधियों पर कलेंडर तैयार करने का निर्णय लिया गया।
4. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन वर्ष मनाने के लिए विभिन्न आयोजनों को शामिल करते हुए एक कलेंडर तैयार और साझा किया है।
5. पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन सहयोग मजबूत बनाने पर आसियान और भारत के बीच 2012 के समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत पर्यटन के क्षेत्र में आसियान-भारत सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में 2018 में किये गये समझौता ज्ञापन को लागू करने के काम में प्रगति पर भी विचार किया गया।
6. इस बैठक में ब्रुनेई ब्रुनेई दारेसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, म्यांमार, फिलिपिंस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा (एसआईएमटीएआरएस) के जरिए महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन खान एवं ऊर्जा विभाग, क्वींसलैंड प्रशासन, ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।

प्रभाव

1. सहमति पत्र से डीजीएमएस और एसआईएमटीएआरएस के बीच साझेदारी कायम करने में मदद मिलेगी:
2. जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, प्रशिक्षण प्रदान करना,
3. सम्मेलन, संगोष्ठीय और अन्यी तकनीकी बैठकों का आयोजन, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वासस्वक् अकादमी और राष्ट्रीय खान आपदा केंद्र की स्थापना तथा
4. डीजीएमएस में आर एंड डी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण।

पृष्ठभूमि

1. ऑस्ट्रेलिया में खान दुर्घटनाओं की दर विश्व में सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया जोखिमों की पहचान और खतरे के आकलन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खान क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की संकल्पकना और कार्यान्वयन के क्षेत्र में अग्रणी है।
2. एसआईएमटीएआरएस खान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विशिष्ट प्रकार की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है।

कार्यान्वीयन संबंधी कार्यनीति

1. यह सहमति पत्र हस्ताक्षर वाली तिथि से ही क्रियाशील हो जाएगा और तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

भारत और मालदीव के बीच समझौता को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच दिसंबर, 2018 में हस्ताक्षरित वीजा प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। वीजा प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते पर मालदीव के

पृष्ठभूमि

1. भारत और मालदीव के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे और परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
2. भारत और मालदीव की जनता के बीच करीबी रिश्ते दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद तैयार करते हैं, जिसे नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए की गई माले यात्रा तथा इसके पश्चात् दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से और भी सकारात्मक गति मिली।

राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

क्या है

1. इस समझौते का उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच जनता के **आपसी संपर्क** को और मजबूत बनाना है। इससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन, इलाज, शिक्षा के साथ ही साथ कारोबार और रोजगार के उद्देश्य से एक दूसरे के यहां आना-जाना आसान हो जाएगा।
2. यह समझौता पर्यटन, इलाज और सीमित कारोबारी उद्देश्य से **90 दिन की वीजा मुक्त यात्रा का प्रावधान** करता है और इस प्रकार के वीजा के बिना प्रवेश को आसानी से मेडिकल वीजा साथ ही साथ छात्रों के आश्रितों और एक दूसरे के क्षेत्र में रोजगार पाने की कोशिश करने वालों के वीजा में आसानी से परिवर्तित करने का भी प्रावधान करता है।

फिलीपीन में जनमत संग्रह

दक्षिणी फिलीपीन के मुस्लिमों ने **एक नए** स्वायत्त क्षेत्र को लेकर हुए जनमत संग्रह में 21 जनवरी 2018 को अपने वोट डाले। इस जनमत संग्रह को 50 वर्षों से चली आ रही अशांति को खत्म करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। यहां के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि स्वायत्त क्षेत्र इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित आतंकवादियों के उदय पर विराम लगाने का सबसे बेहतर विकल्प है।

क्या है

1. इस वोट को मनीला की सरकार और मुख्य विद्रोही समूह मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के शांति प्रयासों को अंतिम रूप देने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है ताकि **2014** में हुए सौदे पर सहमति बन सके।
2. इस सौदे पर हस्ताक्षर **2014** में हुए थे, लेकिन पिछले साल आखिरकार स्वीकृत होने से पहले यह फिलीपीन की कांग्रेस में काफी समय तक लंबित पड़ा रहा।
3. आईएस से जुड़े आतंकवादियों द्वारा मारावी शहर में हिंसा और दक्षिण में हुए विस्फोट एवं हमलों के जरिए इस सौदे को नाकाम करने की कोशिश की गई थी।
4. मोरो समूह के प्रमुख अल हज मुराद इब्राहिम हमेशा से कहते रहे हैं कि मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र बनाना मिन्दनाओ (अल्पसंख्यक मुस्लिमों के गढ़) में आईएस से जुड़े छोटे-छोटे कई कट्टर समूहों के खात्मे का सबसे सटीक तरीका है।

भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में **भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी)** को अपनी स्वीकृति दे दी है।

लाभ

1. भारत और जापान के बीच **खाद्य प्रसंस्करण** क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को परस्पर लाभ मिलेगा।
2. इससे दोनों देशों में खाद्य प्रसंस्करण में श्रेष्ठ व्यवहारों की समझदारी बढ़ेगी और गुणवत्ता के साथ बाजार पहुंच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सुधार में सहायता मिलेगी।
3. सहयोग ज्ञापन से **नवाचारी तकनीक और प्रक्रियाओं** को अपना कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बेहतर होगा। इससे श्रेष्ठ व्यवहारों और बेहतर बाजार तक पहुंच बनाकर देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

चीन ने चांद पर उपजाया कपास

एक तरफ जहां पृथ्वी कई जगह फसल उपजाने में मुश्किलें आ रही हैं, वहीं चीन ने चांद पर **कपास** के बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है। चीन की ओर से चांद पर भेजे गए रोवर पर कपास के बीज अंकुरित हुए हैं। यह पहला

मौका है, जब इंसानों की दुनिया से परे चांद पर कोई पौधा पनप रहा है। वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी। चीन को अब यहां आलू उपजाने की भी उम्मीद है।

क्या है

1. चोंगकिंग विश्वविद्यालय के अडवांस्ड टेक्नॉलजी रिसर्च इंस्टिट्यूट से जारी तस्वीरों की सीरीज के मुताबिक, चांग E-4 के इस महीने चंद्रमा पर उतरने के बाद यह अंकुर एक कनस्तर के भीतर मौजूद जालीनुमा ढांचे से पनपा है।
2. प्रयोग के डिजाइन की अगुवाई करने वाले शाइ गेंगशिन ने कहा, शयं पहला मौका है, जब **मानव** ने चंद्रमा की सतह पर जीवविज्ञान में पौधों के विकास के लिए प्रयोग किए।
3. अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की चीन की महत्वाकांक्षा बढ़ाते हुए चांग E-4 तीन जनवरी को चंद्रमा के सबसे दूर के हिस्से में उतरा और प्राकृतिक उपग्रह के कभी न देखे गए हिस्से तक पहुंचने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान बन गया।
4. चोंगकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वायु, जल और मिट्टी युक्त 18 सेंटीमीटर का एक बाल्टीनुमा डिब्बा भेजा था। इसके भीतर कपास, आलू और सरसों प्रजाति के एक एक पौधे के बीज के साथ-साथ फ्रूट फ्लाय के अंडे और ईस्ट भेजे गए।
5. यूनिवर्सिटी ने बताया कि अंतरिक्षयान से भेजी गई तस्वीरों में देखा गया कि कपास के अंकुर बढ़िया से विकसित हो रहे हैं, लेकिन अब तक अन्य पौधों के बीजों के अंकुरित होने की खबर नहीं है।

अर्थशास्त्र

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में **केन्द्रीय मंत्रिमंडल** ने **वस्तु एवं सेवा कर** अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के **गठन को मंजूरी** दे दी है। **अपीलीय अधिकरण** की राष्ट्रीय पीठ **नई दिल्ली** में स्थित होगी। जीएसटीएटी की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे। जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर एकमुश्त व्यय 92.50 लाख रुपये का होगा, जबकि आवर्ती व्यय सालाना 6.86 करोड़ रुपये होगा।

क्या है

1. वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जीएसटी **कानूनों में दूसरी अपील** का मंच है और केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम समान मंच है।
2. केन्द्र और राज्य, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रथम अपीलों में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील, जीएसटी अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल होती है जो कि केन्द्र तथा राज्य जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत एक होता है।
3. समान मंच होने के कारण जीएसटी अपीलीय अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एकरूपता होगी और इस प्रकार समूचे देश में जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
4. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय गटप्प में जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत **विवाद समाधान हेतु** अपीलीय और **समीक्षा तंत्र** की व्यवस्था की गई है।
5. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करती है कि वह परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा सिफारिश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी बनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर अपील के रूप में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूजीकरण को स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूजीकरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूजीकरण बांड जारी करेगी। वित्त वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये की दो किस्तों के जरिए इक्विटी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। पुनर्पूजीकरण बांड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए जाएंगे।

प्रमुख प्रभाव

1. एक्जिम बैंक भारत के लिए प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है।
2. एक्जिम बैंक में पूंजी लगाने से यह पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने और इसके साथ ही ज्यादा क्षमता के साथ भारतीय निर्यात के लिए आवश्यक सहायता देने में समर्थ हो जाएगा।
3. नई पूंजी लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने, रियायती वित्त योजना (सीएफएस) में संभावित बदलावों, भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में नई ऋण रेखा (एलओसी) की संभावनाओं जैसी नई पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि

1. एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
2. यह बैंक मुख्यतः भारत से निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत से विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी इसमें शामिल है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का इन्सॉल्वेन्सी एंड दिवालियापन कोड को लेकर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड (आइबीसी) को संपूर्ण बनाए रखने का फैसला सुनाया है। यह एक क्रांतिकारी कानून है। आइबीसी कानून में बाजार आधारित और समय सीमा के तहत इन्सॉल्वेन्सी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है। हालांकि समय सीमा का पालन नहीं हो पाना और मामलों को स्वीकार करने में होने वाली अत्यधिक देरी इससे जुड़ी कुछ बड़ी समस्याएं हैं।

क्या है

1. कंपनी मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने आइबीसी के कार्यान्वयन को मिलीजुली सफलता बताया था। श्रीनिवास ने कहा कि यह कानून निश्चित रूप से क्रांतिकारी साबित हुआ है।
2. उन्होंने कहा कि इस कानून के कारण प्रक्रिया के तहत मामले को स्वीकार किए जाने से पहले ही निपटारा होने लगे हैं और कई मामलों में फंसे कर्ज पर भुगतान शुरू हो गया है।
3. इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 29 के मुताबिक, बाहरी व्यक्ति ही कंपनी खरीद सकता है।
4. दूसरी ओर 500 से 1000 करोड़ रुपये तक के मामलों में थर्ड पार्टी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं। ऐसे में ये मामले लंबे समय के लिए अटक जाते हैं। इसलिए इन मामलों में बैंक अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं।

अमेजन के सौदे को सीसीआई की मंजूरी

सुपरमार्केट स्टोर चेन मोर का संचालन करने वाली आदित्य बिरला रिटेल लि. का अधिग्रहण करने के अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की हरी झंडी मिल गई। सौदे के तहत समारा कैपिटल समर्थित विटजिग एडवायजरी सर्विसेज और अमेजन की सब्सिडियरी कंपनी आदित्य बिरला रिटेल का अधिग्रहण करेगी। यह सौदा 4,200 करोड़ रुपये में होने की बात कही गई है।

क्या है

1. सीसीआई के अनुसार आदित्य बिरला रिटेल की 99.99 फीसद हिस्सेदारी विटजिग खरीदेगी। विटजिग की 49 फीसद हिस्सेदारी अमेजन की सब्सिडियरी अमेजन एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएससी अधिग्रहीत करेगी। देश के रिटेल स्टोर फॉर्मेट में अमेजन का यह दूसरा निवेश है।
2. इससे पहले उसने के. रहेजा ग्रुप की रिटेल कंपनी शॉपर स्टॉप को खरीदा था। विटजिग समारा आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह सेबी में कैटागरी-2 आल्टरनेटिव फंड के तौर पर पंजीकृत है।
3. सीसीआई ने ट्वीट करके बताया कि विटजिग एडवायजरी सर्विसेज द्वारा आदित्य बिरला रिटेल की 99.99 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
4. उसने कहा कि उसने विटजिग की 49 फीसद हिस्सेदारी अमेजन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
5. अमेजन ने प्रतिस्पर्धा नियामक को दिए नोटिस में बताया कि विटजिग की 49 फीसद हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद 51 फीसद बहुमत हिस्सेदारी समारा फंड के पास रहेगी।

भारत सरकार और जेआईसीए ने ऋण समझौता पर हस्ताक्षर

जापान के सरकारी विकास सहायता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में भारत सरकार और जेआईसीए के बीच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव डॉ. सी. एस. महापात्र तथा जापानी अधिकारिक विकास सहायता ऋण पर जेआईसीए, नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि श्री कतसुओ मत्सुतमोतो ने हस्ताक्षर किए। जापान द्वारा यह ऋण (प) 40.074 बिलियन जापानी येन (लगभग 2470 करोड़ रुपये) की लागत से चेन्नई बाहरी रिंग रोड (चरण-1) के निर्माण के तथा (पप) 15000 बिलियन जापानी येन (लगभग 950 करोड़ रुपये) की भारत में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्य के लिए है।

क्या है

1. चेन्नई बाहरी रिंग रोड (चरण-1) निर्माण परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगर क्षेत्र में बढ़ते यातायात मांग को पूरा करना है, जिसे चेन्नई बाहरी रिंग रोड (सेक्टर-1) बनाकर तथा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट प्रणाली स्थापित करके किया जा सकता है। इससे यातायात भीड़-भाड़ में कम होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2. भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों का उद्देश्य भारत में एसडीजी के प्रोत्साहन में योगदान करना, विशेषकर भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन देकर सामाजिक विकास करना और नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन व्य. वस्था को मजबूत बनाना है।
3. भारत और जापान के बीच 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग का लम्बा इतिहास रहा है। भारत-जापान आर्थिक सहयोग में तेजी से प्रगति हुई है। यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था निगरानी रिपोर्ट

वैश्विक सलाहकार कंपनी पीडब्ल्यूसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी विकास दर के प्रति बेहद उत्साहजनक अनुमान लगाया है। अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि भारत इसी वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ पांचवें स्थान पर आ सकता है। विश्व बैंक के मुताबिक **भारत अभी छठी सबसे बड़ी** अर्थव्यवस्था है।

क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग समान विकास दर और **आबादी के कारण** ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में आगे-पीछे होते रहते हैं।
2. लेकिन यदि भारत इस सूची में आगे निकलता है तो उसका स्थान स्थायी रहेगा। पीडब्ल्यूसी की वैश्विक **अर्थव्यवस्था निगरानी रिपोर्ट** में अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष ब्रिटेन की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 1.6 फीसद, फ्रांस की 1.7 फीसद तथा **भारत की 7.6 फीसद** रहेगी।
3. रिपोर्ट का कहना है कि इस वर्ष भारत और फ्रांस दोनों ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे। इससे वैश्विक रैंकिंग में ब्रिटेन पांचवें स्थान से फिसलकर सातवें पायदान पर चला जाएगा।
4. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
5. 2017 में भारत 2,590 अरब डॉलर के बराबर जीडीपी के साथ फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। उस वर्ष 2,580 अरब डॉलर जीडीपी के साथ फ्रांस सातवें स्थान पर था। जल्द भारत के ब्रिटेन को पीछे छोड़ने की उम्मीद है, जो अभी पांचवें स्थान पर है।

देश से ज्यादा है दर्जनभर राज्यों की सालाना आर्थिक विकास दर

दर्जनभर **राज्यों की** सालाना आर्थिक विकास दर **देश की** विकास दर से ज्यादा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल की आर्थिक विकास दर बेहतरीन रही है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11.3 फीसद के साथ बिहार की विकास दर देश में सबसे ज्यादा रही है। गत वर्ष देश की विकास दर 6.7 फीसद थी। देश की दो प्रमुख रेटिंग एजेंसी **इंडिया रेटिंग्स** और **क्रिसिल** ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकांश राज्यों की स्थिति पिछले पांच वर्षों में सुधरी है। हालांकि **राजकोषीय घाटे** को लेकर इन राज्यों को अभी काफी सतर्कता बरतनी है।

क्या है

1. इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि **राजकोषीय घाटे** में **सुधार** के लक्षण हैं। लेकिन चुनावी साल में अगर राजनीतिक लोक लुभावन नीतियां अपनाई गईं तो इस पर पानी फिर सकता है। खासतौर पर जिस तरह से कई राज्यों में **कृषि कर्ज माफी** को लागू किया गया है वह अच्छा संकेत नहीं है।
2. यही वजह है कि संस्था ने वर्ष 2018-19 के लिए राज्यों के समग्र राजकोषीय घाटे का अनुमान पूर्व के 2.8 फीसद से बढ़ाकर 3.2 फीसद कर दिया है।
3. इंडिया रेटिंग्स मानता है कि आम चुनाव के साल में लोक लुभावन नीतियों या अन्य वित्तीय घोषणाओं से मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश होगी।
4. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ करने की कुछ योजनाएं लागू की हैं। इनके अलावा झारखंड और तेलंगाना में भी किसानों को राहत देने का एलान किया गया है। पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में पहले से ही ऐसा हो रहा है।
5. क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले पांच वर्षों के औसत आधार पर **गुजरात** सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाला, महंगाई को बेहतर तरीके से काबू करने वाला और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने वाला राज्य बना हुआ है।

6. उसके बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार का स्थान है। लेकिन बिहार का राजकोषीय घाटा 7.2 फीसद है, जो चिंता का कारण है।
7. मध्य प्रदेश एक वर्ष के भीतर सातवें स्थान से खिसक कर 10वें स्थान पर चला गया है। अब जबकि वहां की नई सरकार किसानों के कर्ज माफ कर रही है, तो हो सकता है कि इस वर्ष उसकी स्थिति और बिगड़ जाए।
8. दोनों रिपोर्ट में इन राज्यों सरकारों से कहा गया है कि उन्हें तेज विकास दर और अपने राज्य की जनता की बेहतरी के लिए राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

TCS दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा देने वाली कंपनी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को 2018-19 में दुनिया का तीसरी सबसे बहुमूल्य आईटी सेवा ब्रांड रैंकिंग मिली है। पहले नंबर पर एसेंचर और दूसरे पर आईबीएम है। ब्रांड फाइनेंसने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। दुनिया की शीर्ष दस कंपनियों में भारत की चार आईटी सेवा देने वाली कंपनियां हैं। इनमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और विप्रो शामिल हैं।

क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की सबसे बहुमूल्य आईटी सेवा ब्रांड एसेंचर है। उसकी ब्रांड मूल्य 26.3 अरब डॉलर है। इससे पहले आईबीएम सबसे बहुमूल्य कंपनी थी। आईबीएम 20.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे पायदान पर आ गई है।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे स्थान पर टीसीएस है, उसका ब्रांड मूल्य 23 फीसद बढ़कर 12.8 अरब डॉलर आंका गया है। विप्रो शीर्ष दस की सूची में पहली बार शामिल हुई है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की सालाना आम बैठक में स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी की गई।
3. ब्रांड फाइनेंस ने कहा कि टीसीएस जापानी बाजार में सफलता हासिल करने वाला पहला भारतीय आईटी सेवा ब्रांड भी है और इसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक ऑटोमेशन का लाभ उठाते हुए एक बेहतर ऑल-राउंड कस्टमर एक्सपीरियंस देने में खुद को आगे रखा है।
4. अमेरिकी ब्रांड कॉग्निजेंट (ब्रांड वैल्यू 12 फीसद से 8.7 अरब डॉलर तक) और भारत की इन्फोसिस (ब्रांड वैल्यू 8 फीसद से 6.5 अरब डॉलर तक) दोनों पिछले साल चौथे और पांचवें स्थान पर रही।

सरकारी बैंकों को मिला बड़ा अधिकार

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े आर्थिक अपराधियों को देश छोड़कर भागने के मामलों को देखते हुए सरकार ने सरकारी बैंकों को बड़ा अधिकार दे दिया है। बैंक अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एलओसी) जारी करने का सीधा अनुरोध कर सकती हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने बीते दिन दी है। गृह मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), एक वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी को भी उस सूरत में एलओसी का अनुरोध करने की इजाजत दे दी है, जिसमें उसे संदिग्ध के देश छोड़कर जाने का शक हो।

क्या है

1. मंत्रालय ने हाल ही में दो सर्कुलर जारी कर सरकारी बैंकों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ ही एसएफआईओ को विलफुल डिफॉल्टर्स के देश छोड़कर भागने के शक की सूरत में एलओसी का निवेदन करने का अधिकार दे दिया है।
2. सरकारी बैंकों के सीएमडी और सीईओ अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क एवं आयकर विभागों, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीबीआई, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों और पुलिस से एलओसी जारी करने को कह सकते हैं ताकि इमीग्रेशन चेक पोस्ट को अलर्ट कर किसी को देश छोड़कर जाने से रोका जा सके।

- अगर एसएफआईओ या सरकारी बैंकों को ऐसा शक हो कि डिफाल्टर्स कानून से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकता है तो वे इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा करने का अधिकार सिर्फ जांच एजेंसियों के पास था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18% बढ़ा

वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 18 प्रतिशत बढ़कर 28.25 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 28 जनवरी 2019 को ये आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक वर्ष के दौरान देश में सबसे ज्यादा निवेश मॉरीशस से आया है। भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की परिसंपत्तियों और विदेशी देनदारियों की गणना संबंधी 2017-18 के आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष विदेश निवेश 4,33,300 करोड़ रुपये बढ़कर 28,24,600 रुपये पर पहुंच गया। इसमें पिछले निवेशों का नया मूल्यांकन भी शामिल है।

क्या है

- रिजर्व बैंक ने कहा कि गणना के हाल के दौर में 23,065 कंपनियों ने पूछे गए सवालों का जवाब दिया, जिसमें से 20,732 कंपनियों ने मार्च 2018 में अपनी बैलेंसशीट में एफडीआई या ओडीआई निवेश को दर्शाया है। इस दौरान भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश (ओडीआई) 5 प्रतिशत बढ़कर 5.28 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरीशस से (19.7 प्रतिशत) हुआ है। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और जापान का स्थान है।
- दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों के विदेश में निवेश के मामले में 17.5 प्रतिशत के साथ सिंगापुर सबसे प्रमुख स्थान रहा। इसके बाद नीदरलैंड, मॉरीशस और अमेरिका का स्थान रहा है।
- कुल एफडीआई में विनिर्माण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा रहा है। इसके अलावा सूचना और दूरसंचार सेवाओं, वित्तीय और बीमा गतिविधियां एफडीआई पाने वाले अन्य प्रमुख क्षेत्र रहे हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

- ग्रीन फील्ड निवेश - इसके तहत दूसरे देश में एक नई कम्पनी स्थापित की जाती है,
- पोर्टफोलियो निवेश - इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है।

फलैशबैक

- किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट / एफडीआई) कहलाता है।
- ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है।
- आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है।
- इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।

दुनिया के टॉप 100 ब्रांड में शामिल हुई टाटा

टाटा दुनिया की 100 वैल्युएबल ब्रांड में शामिल हो गई है। कंपनी की वैल्यू 2019 में 37 फीसद बढ़कर 19.5 बिलियन डॉलर हो गई, जिसके बाद टाटा को दुनिया के टॉप 100 ब्रांड में 86वां स्थान मिला है। साल्ट-टू-सॉफ्टवेर आधारित समूह को लंदन स्थित कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की ओर से 86वें स्थान दिया गया, यह ग्लोबल टॉप 100 में एकमात्र घरेलू ब्रांड है।

क्या है

1. ब्रांड फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी डेविड है ने एक बयान में कहा, 'टाटा समूह ने 2019 में ब्रांड मूल्य में बहुत अच्छी वृद्धि की है, और दुनिया में टॉप 100 में सबसे मूल्यवान ब्रांडों में एकमात्र भारतीय ब्रांड होने के कारण इसे पुरस्कृत भी किया गया है।'
2. इस रिपोर्ट के बाद टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा, 'हमें कुछ नया और उद्यमिता के माध्यम से बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करने होंगे, इससे हमें सामाजिक रूप से वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय को चलाने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा।'
3. टाटा के ब्रांड वैल्यू में सुधार में काफी हद तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी योगदान रहा है। एक बयान में कहा गया है कि समूह के ब्रांड मूल्य में मोटर वाहन और इस्पात कंपनियों का भी योगदान रहा है।

फलैशबैक

1. टाटा समूह एक निजी व्यवसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष रतन टाटा हैं।
2. टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने 28 दिसम्बर 2012 को सायरस मिस्त्री को टाटा समूह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
3. रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े हैं वे 21 सालों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। रतन टाटा ने जे आर डी टाटा के बाद 1991 में कार्यभार संभाला।
4. टाटा परिवार का एक सदस्य ही हमेशा टाटा समूह का अध्यक्ष रहा है। इसका कार्यक्षेत्र अनेक व्यवसायों व व्यवसाय से सम्बंधित सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है - जैसे: अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, वाहन, रासायनिक उद्योग, ऊर्जा, सॉफ्टवेयर, होटल, इस्पात एवं उपभोक्ता सामग्री।

विज्ञान एवं तकनीकी

विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहल की शुरुआत

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने दूरदर्शन (डीडी), प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्ली में विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों यथा 'डीडी साइंस' और 'इंडिया साइंस' की शुरुआत की। डीडी साइंस दरअसल दूरदर्शन न्यूज चैनल पर एक घंटे का स्लॉट है, जिसका प्रसारण सोमवार से शनिवार तक सायं 05:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जाएगा। इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपलब्ध है और यह मांग पर निर्धारित वीडियो लाइव उपलब्ध कराएगा।

क्या है

1. केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इन दोनों महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए कहा कि यह न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार, बल्कि हमारे समाज की वैज्ञानिक सोच विकसित करने के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पल है।
2. भारत की सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन द्वारा नब्बे के दशक में पल्सा पोलियो अभियान में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की 92 प्रतिशत से भी अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने वाला दूरदर्शन विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम साबित होगा।
3. डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में देश में चौबीसों घंटे चलने वाले 'डीडी साइंस चैनल' का शुभारंभ होगा। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'वर्ष 2030 तक हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष तीन देशों में शुमार होना होगा और इस तरह की पहल इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास हैं।'

- विज्ञान संचार से जुड़े दो प्लेसटफॉर्म विज्ञान को बढ़ावा देने और इसे रोजमर्रा की जिंदगी के करीब लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल के रूप में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और दूरदर्शन का उद्देश्य **मानवता की सेवा** के लिए देश में इनकी सार्थकता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना तथा विज्ञान को और आगे ले जाना है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने इन चैनलों की परिकल्पना करने के साथ-साथ इन्हें मूर्तरूप देने में काफी सहयोग प्रदान किया है। इनका कार्यान्वयन एवं प्रबंधन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है, जो डीएसटी का एक स्वायत्त संगठन है।
- भारत में विज्ञान संचार के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले ये दोनों विज्ञान चैनल देश में एक राष्ट्रीय विज्ञान चैनल का आगाज करने की दिशा में आरंभिक कदम हैं। जहां एक ओर इंडिया साइंस (पदकपेंबपमदबम.पद) ने पहले से ही चौबीसों घंटे वाली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है, वहीं दूसरी ओर डीडी साइंस को भी भविष्य में एक पूर्ण चैनल में तब्दील किया जा सकता है।
- इन दोनों चैनलों के जरिये विज्ञान आधारित वृत्तचित्र, स्टूडियो-आधारित परिचर्चाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों के आभासी पूर्वाभ्यास, साक्षात्कार और लघु फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये दर्शकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होंगे।

एचएएल ने तैयार किया हल्का लड़ाकू हेलिकॉप्टर

देश में हथियारों का निर्माण करने वाली सरकारी कंपनी **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)** द्वारा डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) से गतिमान हवाई निशाने पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का **सफल परीक्षण** किया गया।

क्या है

- एलसीएच पर अन्य हथियारों में 20मिमी गन और 70 मिमी रॉकेट शामिल हैं, जिनमें से फायरिंग ट्रायल पिछले साल ही पूरा हो चुका है।
- वित्तीय संकट का सामना करने की खबरों सामने आने के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले दिनों बताया था कि 83 हल्के लड़ाकू विमानों और 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर अभी अंतिम चरण में हैं और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावनाएं हैं।
- एचएएल ने यह भी कहा था कि उसने अपनी मौजूदा जरूरतें पूरी करने के लिए 962 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट (बैंक से धनराशि लेना) लिया था।

ISRO लॉन्च कर रहा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख के. सिवन ने बताया है कि इसरो **एक महीने का युवा विज्ञानी कार्यक्रम लॉन्च कर रही है**। इस कार्यक्रम के तहत **प्रत्येक राज्य** से तीन विद्यार्थी चुने जाएंगे। इन्हें शिक्षित किया जाएगा और शोध तथा विकास प्रक्रिया से **जुड़ी प्रयोगशालाओं** तक उनकी पहुंच बनाई जाएगी, ताकि वे उपग्रह बनाने का वास्तविक अनुभव हासिल हो सके। इसरो प्रमुख ने बताया कि हमने त्रिपुरा में इनक्यूबेशन सेंटर विकसित किया है और त्रिची, नागपुर, राउरकेला तथा इंदौर में चार और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। गगनयान मिशन को लेकर इसरो चेयरमैन के सिवन ने कहा, श्रद्धा साल गगनयान मिशन हमारी प्राथमिकता रहेगी और गृह मंत्रालय की मदद के लिए भी सैटलाइट लॉन्च की जाएगी। साल 2019 में इसरो बॉर्डर सिक्वॉरिटी सैटलाइट लांच **करेगा। 2020 में पहला मानव रहित मिशन और 2022 में दूसरा मानव रहित मिशन पूरा किया जाएगा।**

क्या है

- गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 10 हजार करोड़ की महत्वकांक्षी **गगनयान परियोजना** को मंजूरी दे दी थी। अगर यह मिशन कामयाब हुआ तो अंतरिक्ष पर मानव मिशन भेजने वाला **भारत** दुनिया का चौथा देश होगा।

2. इस प्रोजेक्ट में मदद के लिए **भारत** ने पहले ही रूस और फ्रांस के साथ करार किया है। अभी तक दुनिया में सिर्फ तीन देश हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा है।
3. इसमें पहली **उपलब्धि** सोवियत संघ (आज के रूस) के नाम है, जिसने 1957 में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। इसकी सफलता से उत्साहित सोवियत संघ ने 12 अप्रैल, 1961 को अपने नागरिक यूरी एलेकसेविच गागरिन को वोस्टॉक-1 नामक यान से स्पेस में भेजा था।
4. इसके बाद से रूस वोस्टॉक, वोस्खोड और सोयूज यानों से करीब 74 मानव मिशनों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसके बाद बारी आई अमेरिका की, जिसने 5 मई, 1961 को अपने नागरिक एलन बी शेपर्ड को प्रोजेक्ट मरकरी मिशन के तहत **स्पेसक्राफ्ट फ्रीडम-7** से अंतरिक्ष में रवाना किया।
5. इसके बाद से अमेरिकी स्पेस एजेंसी-नासा 200 से ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज चुकी है। यह करिश्मा करने वालों की सूची में तीसरा देश चीन है, जिसने 15 अक्टूबर, 2003 को अपने नागरिक यांग लिवेई को शिंझोऊ-5 यान से अंतरिक्ष में भेजा था। वैसे तो इस अवधि में कई अमीर पर्यटक भी स्पेस टूरिज्म के तहत अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं और आने वाले वक्त में संभवतः दर्जनों लोग निजी कंपनियों की मदद से स्पेस की यात्रा का आनंद ले सकेंगे, लेकिन जो बात देश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वदेशी यानों से अंतरिक्ष में पदार्पण करने में है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है।

शनि के छल्लों की उम्र खुद शनि से भी बहुत कम

शनि के छल्ले वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से बहुत कम उम्र के हैं और वे पिछले एक से 10 करोड़ साल के बीच ही **नजर आने शुरू** हुए थे। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैसिनी अंतरिक्षयान से मिले खोज परिणामों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। सूरज से **छठे स्थान पर मौजूद ग्रह** का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था और उसके अस्तित्व का अधिकतम समय उन विशेष छल्लों के बिना ही बीता है जिसके लिए उसे आज जाना जाता है।

क्या है

1. खगोलविदों का मानना है कि संभवतः **शनि के चंद्रमाओं के बीच टकराव** या एक धूमकेतु के कारण इसका निर्माण हुआ जो ग्रह के करीब ही आ कर बिखरा हो सकता है।
2. इनमें से कुछ सवालों के जवाब कैसिनी के कारण मिल सके हैं। यह अमेरिकी-यूरोपीय अंतरिक्षयान 1997 में भेजा गया था और 2017 में शनि की सतह पर नियोजित ढंग से खत्म हो गया था।
3. मिशन के अंत में कैसिनी 22 बार **शनि** एवं उसके छल्लों के बीच परिक्रमा कर इतिहास के किसी भी अंतरिक्षयान के मुकाबले उनके सबसे करीब गया।
4. कैसिनी का उड़ान पथ इन छल्लों के गुरुत्वाकर्षण से कैसे प्रभावित हुआ, इसका अध्ययन कर वैज्ञानिक इन छल्लों के भार एवं अनुमानित उम्र का पता लगा सके।
5. सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रमुख अनुसंधानकर्ता लुसियानो लेस ने कहा कि कैसिनी के अंतिम कक्ष में शनि के इतने करीब जाने से ही हम नई खोजों के लिए माप ले सके।

शनिग्रह पर 10 घंटे का होता है दिन

नासा कैसिनी अंतरिक्षयान ने आखिरकार इस गुथी को सुलझा लिया है कि शनिग्रह पर कितने घंटे का दिन होता है। नासा ने सौरमंडल विज्ञान की इस गुथी को सुलझाते हुए बताया कि **शनिग्रह** पर सिर्फ साढ़े 10 घंटे का दिन होता है। कैसिनी मिशन अब वजूद में नहीं है, लेकिन उससे प्राप्त नए डेटा का उपयोग करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया-शांता क्रूज की

अगुवाई में वैज्ञानिकों ने बताया कि शनिग्रह पर एक साल पृथ्वी के 29 साल के बराबर होता है। लेकिन दिन सिर्फ 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड का होता है।

क्या है

1. लोग अब तक इस तथ्य से अनजान थे, क्योंकि यह छल्ले में छिपा हुआ था। यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के छात्र क्रिस्टोफर मैकोविज ने छल्ले के भीतर की तरंग के पैटर्न का विश्लेषण किया।
2. नतीजों में पाया गया कि खुद ग्रह के भीतर होने वाले कंपनी से उसमें उसी तरह की प्रतिक्रिया मिलती है, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भूकंप की माप के लिए सिस्मोमीटर में मिलती है। शनिग्रह के भीतर लगातार कंपन होता है, जिससे उसके गुरुत्वाकर्षण में बदलाव होता है। छल्ले से उस गति का पता चलता है।
3. छल्ले में किसी खास स्थान पर यह दोलन छल्ले के कण को आकर्षित करता है, जिससे कक्षा में सही समय पर ऊर्जा का निर्माण होता है।
4. मैकोविज का यह शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ हुआ है। शोध में शनिग्रह के आंतरिक मॉडल के बारे में बताया गया, जो छल्ले के तरंग की तरह है। इससे उनको ग्रह की आंतरिक गतिविधि और घूर्णन के बारे में पता चला है।

चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया बंदरों का क्लोन

चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर जैसे कई रोगों के अध्ययन के लिए जीन में बदलाव कर पांच बंदरों का क्लोन तैयार किया है जन्म दिया है और दावा किया है कि इससे मेडिकल रिसर्च में मदद मिलेगी। हालांकि, इससे जीन में बदलाव को लेकर नए सिरे से नैतिक चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

क्या है

1. कुछ दिन पहले ही जीन में बदलाव कर दुनिया के पहले मानव शिशु को जन्म देने का दावा चीन के वैज्ञानिकों ने किया था और इस अनधिकृत प्रयोग को लेकर वैज्ञानिक जगत में उथल-पुथल मच गई थी।
2. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अब चीन के वैज्ञानिकों ने नींद की समस्या, अवसाद और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े विकारों वाले एक बंदर के जीन में बदलाव कर उसके पांच क्लोन बनाए।
3. एजेंसी के मुताबिक, पहली बार जैवचिकित्सकीय रिसर्च के लिए बंदर के जीन बदलकर कई क्लोन बनाए गए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली चीन की शीर्ष पत्रिका शैशनल साइंस रिव्यू में प्रकाशित दो लेखों के साथ गुरुवार को बंदर की क्लोनिंग की घोषणा की।
4. क्लोनिंग के माध्यम से बच्चों को शंघाई स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस में जन्म दिया गया।

फसलों पर आर्सेनिक के असर को रोकेगा यह बैक्टीरिया

भारतीय वैज्ञानिकों ने विशेष सूक्ष्मजीवों की ऐसी 150 प्रजातियां ढूंढ निकाली हैं, जो पानी-मिट्टी में मौजूद जहरीले तत्वों को सोख लेने में माहिर हैं। ये सूक्ष्मजीव भारी धातुओं और रसायनों आदि को हजम कर फसलों में जाने से रोक देते हैं। इनमें से कुछ तो इतने विलक्षण हैं कि वे एक ही नहीं बल्कि सभी नौ भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा हजम करने में दक्ष पाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो (नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, एनबीएआइएम) की यह खोज फसलों को रसायन मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी का संकेत है। प्रयोग पूरी तरह सफल रहा तो आर्सेनिक, लेड और अन्य भारी धातुओं से प्रभावित क्षेत्रों में भी खाने योग्य फसलें लहलहाएंगी। उन क्षेत्रों का कायाकल्प शुरू हो जाएगा।

क्या है

1. आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम, कॉपर, निकिल, जिंक आदि भारी धातुएं न सिर्फ मिट्टी और जल के धात्विक प्रदूषण का कारक हैं, बल्कि इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति भी मानव, वनस्पति व जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।
2. इन भारी धातुओं से प्रभावित क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां भी खाने योग्य नहीं रह जातीं। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल ढूँढ लिया है।
3. मऊ, उत्तर प्रदेश के कुशमौर स्थित राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो के वैज्ञानिकों ने जब इन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कृषि में किया तो चौंकाने वाले परिणाम मिले। पालक में प्रयोग सफल रहा। सूक्ष्मजीवों ने जल व मिट्टी में व्याप्त भारी धातुओं को सोख कर उन्हें फसल में जाने से रोक दिया।

आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में मिले ये सूक्ष्मजीव

1. इस परियोजना पर काम कर रही ब्यूरो की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. रेणु बताती हैं कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में उगने वाली फसलों, खासकर सब्जियों और फलों में यह जहर भर जाता है और वे खाने योग्य नहीं रह जातीं। यह एक बड़ी समस्या थी।
2. हमने जब इस पर प्रयोग शुरू किया तो पड़ोसी जनपद बलिया, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहां से पानी और मिट्टी के नमूने लिए।
3. यहां ब्यूरो में लाकर जब उन नमूनों में मौजूद सूक्ष्मजीवों को अलग कर उनके गुणों को परखा तो लगभग 150 बैक्टीरिया ऐसे मिले जो इन भारी धातुओं का भोजन करते हैं यानी उन्हें अवशोषित कर हजम करने की क्षमता रखते हैं।
4. इसके बाद इनका प्रयोग पालक के पौधों पर किया गया तो सकारात्मक परिणाम मिले। इन सूक्ष्मजीवों ने इन जहरीले तत्वों को पौधे में पहुंचने से रोक दिया। रेणु कहती हैं, यह प्रयोग उत्साहित करने वाला है और अब अन्य फसलों पर भी इसके बेहतर रिजल्ट देखे जा रहे हैं।
5. आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में हमें सूक्ष्मजीवों की ऐसी 150 प्रजातियां मिली हैं, जो मिट्टी-पानी में मौजूद भारी धातुओं और रसायनों को हजम करने में माहिर हैं। इनमें से कुछ तो इतने विलक्षण हैं कि वे सभी नौ भारी धातुओं को अवशोषित कर ले रहे हैं। इन्हें लेकर कृषि में किया गया शुरुआती प्रयोग सुखद परिणाम देने वाला रहा है। सूक्ष्मजीवों ने विषाक्त कणों को फसलों में जाने से रोक दिया।
6. पर्यावरण में धातु उपचार पारंपरिक भौतिक, रासायनिक तकनीकों, जैसे कि फिल्टरेशन, एसिड लिचिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया या आयन एक्सचेंज द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इन सूक्ष्मजीवों की खोज से अब कम लागत में और पर्यावरण के अनुकूल कारगर तरीका सामने आ सकता है।

देशभर में पांव पसार रहा स्वाइन फ्लू

इन दिनों उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़त पर हैं। वायरस से होने वाली यह बीमारी लापरवाही बरतने पर गंभीर रूप अख्तियार कर सकती है, लेकिन सुखद बात यह है कि इसका समय रहते कारगर इलाज संभव है। आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाने वाला इन्फ्लूजा एक विशेष प्रकार के वायरस इन्फ्लूजा 'ए' एच1 एन1 के कारण फैल रहा है। यह वायरस सुअर में पाए जाने वाले कई प्रकार के वायरस में से एक है। सुअर के शरीर में इस वायरस के रहने के कारण ही इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। वायरस के 'जीन्स' में स्वाभाविक तौर पर परिवर्तन होते रहते हैं। फलस्वरूप इनके आवरण की संरचना में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

क्या है

1. 2009 में फैले स्वाइन फ्लू के कारण इन्फ्लूजा 'ए' टाइप के एक नए वायरस एच1 एन 1 के कारण यह बीमारी फैल रही है। 1918 की फ्लू महामारी में वायरस का स्रोत सुअर थे।

2. इस फ्लू को **स्पेनिश फ्लू** के नाम से जाना जाता है। जीन परिवर्तन से बनी यह किस्म ही मैक्सिको, अमेरिका और पूरे विश्व में स्वाइन फ्लू के प्रसार का कारण बन रही है।
3. स्वाइन फ्लू का संक्रमण व्यक्ति को स्वाइन फ्लू के रोगी के संपर्क में आने पर होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को स्पर्श करने (जैसे हाथ मिलाना), उसके छींकने, खांसने या पीड़ित व्यक्ति की वस्तुओं के संपर्क में आने से स्वाइन फ्लू से कोई व्यक्ति ग्रस्त होता है।
4. खांसने, छींकने या आमने-सामने निकट से बातचीत करते समय रोगी से स्वाइन फ्लू के वायरस दूसरे व्यक्ति के श्वसन तंत्र (नाक, कान, मुंह, सांस मार्ग, फेफड़े) में प्रवेश कर जाते हैं।
5. अनेक लोगों में यह संक्रमण बीमारी का रूप नहीं ले पाता या कई बार सर्दी, जुकाम और गले में खराश तक ही सीमित रहता है।
6. स्वाइन फ्लू के सामान्य लक्षणों के जटिल होने से रोगी को लोअर रेस्पाइटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, डीहाइड्रेशन और निमोनिया हो सकता है। ऐसी स्थितियों में रोगी की जान खतरे में पड़ सकती है।

जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट

देश भर में जन्म के समय लिंगानुपात में **कथित गिरावट** पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छभ्त्) ने महिला एवं बाल विकास (ब्व) मंत्रालय समेत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इस मुद्दे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों से टिप्पणी एवं सुझाव मांगे हैं तथा उन्हें जन्मों की रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण की श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में बताने को कहा है।

क्या है

1. आयोग ने मीडिया की खबरों का गंभीरता से संज्ञान लिया है। इस खबर में देश भर में खासकर **दक्षिण राज्यों** में बिगड़ते लिंगानुपात का मुद्दा उठाया गया है।
2. आयोग ने बयान में कहा कि खबर के अनुसार भारतीय महापंजीयक कार्यालय द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स (बै) से जुटाए गए आंकड़ों से खुलासा होता है कि 2016 में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जन्म के समय लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1000 पर 806 रहा।
3. तमिलनाडु में 2007 में यह अनुपात प्रति 1000 पर 935 था जो 2016 में घटकर 840 हो गया। अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 1000 पर 877 था। कर्नाटक में यह अनुपात प्रति 1000 पर 1004 से घटकर 896 हो गया तथा तेलंगाना में यह प्रति 1000 पर 881 रहा।
4. आयोग ने कहा कि उसे पता है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने बालिकाओं को बचाने और लिंग संबंधी समीकरण में सुधार के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की और उन्हें लागू किया है लेकिन इस खबर के आंकड़े भिन्न तस्वीर पेश करते हैं।

विविध

भारत रत्न 2019

केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को **भारत रत्न** देने का ऐलान किया है। **नानाजी देशमुख** और **भूपेन हजारिका** को मरणोपरांत यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। 20 वर्ष बाद दो से ज्यादा हस्तियों को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है। इससे पहले 1999 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, सितार वादक पंडित रविशंकर, अर्थशास्त्री डॉ. अमर्त्य सेन और स्वतंत्रता सेनानी रहे **गोपीनाथ बोरदोलोई** को इस सम्मान के लिए चुना गया था। चार साल बाद भारत रत्न की घोषणा हुई है। इससे पहले 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** और स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक **मदन मोहन**

मालवीय को यह सम्मान दिया गया था। इससे पहले 45 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। अब यह संख्या 48 हो गई है।

प्रणब मुखर्जी

1. प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के **मिराती** में हुआ था। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया।
2. इसके बाद 1982 में उन्हें कैबिनेट में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। 1984 में राजीव गांधी से मतभेदों के बाद उन्होंने एक **नई राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी** का गठन किया। हालांकि, 1989 में यह पार्टी कांग्रेस में ही शामिल हो गई। इसके बाद पीवी नरसिम्हाराव की सरकार में उन्हें 1991 में योजना आयोग का प्रमुख और 1995 में विदेश मंत्री का कार्यभार दिया गया।
3. 2004 की यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी पहली बार **लोकसभा चुनाव** जीते। 2004 से 2006 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2006-09 तक विदेश मंत्रालय और 2009-12 तक उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई।
4. 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए **नामित** किया। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने पीए संगमा को हराया।
5. प्रणब 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले करीब 5 दशक तक वह कांग्रेस में रहे थे।

नानाजी देशमुख

1. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक, समाजसेवी और **भारतीय जनसंघ** के नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक छोटे से कस्बे में 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था।
2. नानाजी बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर समाज सेवा के क्षेत्र में आए।
3. इसके बाद संघ के सरसंघचालक डॉ. केवी हेडगेवार के संपर्क में आए और फिर संघ के विभिन्न प्रकल्पों के जरिए पूरा जीवन राष्ट्रसेवा में लगा दिया। मध्यप्रदेश का चित्रकूट उनकी कर्मभूमि बना।
4. 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्हें **मोरारजी-मंत्रिमंडल** में शामिल किया गया। लेकिन उन्होंने यह कहकर पद टुकरा दिया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें।
5. वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अटलजी के कार्यकाल में ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2010 को 95 वर्ष की आयु में नानाजी का निधन हो गया।

भूपेन हजारिका

1. 8 सितंबर 1926 में असम के **सादिया** जिले में जन्मे भूपेन हजारिका की स्कूली शिक्षा गुवाहाटी में हुई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया।
2. 1949 में वह स्कॉलरशिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। यहीं पर उनकी मुलाकात प्रियंवदा पटेल से हुई। 1950 में उन्होंने प्रियंवदा से शादी की थी।
3. 1952 में उनके बेटे तेज का जन्म हुआ था। 1953 में हजारिका भारत लौटे। 5 नवंबर 2011 को उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।

अवॉर्ड्स की हैट-ट्रिक

क्रिकेट के मैदान पर नए मुकाम छू रहे विराट कोहली ने अब अवॉर्ड्स का रेकॉर्ड भी बना डाला है। भारतीय टीम के कप्तान कोहली ICC के सालाना पुरस्कारों में व्यक्तिगत सम्मानों की श्रेणी में क्लीन स्वीप करने वाले **पहले क्रिकेटर** बन गए हैं। उन्होंने टेस्ट, वनडे और साल के ओवरऑल बेस्ट प्लेयर का अवॉर्ड **अपने नाम** किया। उन्हें आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भरे टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान भी घोषित किया। कोहली को ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द इयर (सर गारिफील्ड सोबर्स ट्रॉफी), आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इयर और आईसीसी पुरुष वनडे **क्रिकेटर ऑफ द इयर** के

खिताब के लिए चुना गया है। क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी क्रिकेटर को एक ही साल यह तीनों प्रतिष्ठित अवॉर्ड के लिए चुना हो।

1. कुल कितने मैच खेले: 37 मैच (13 टेस्ट, 14 वनडे, 10 T-20), 47 पारियां
2. कितने रन बनाए: 2,735 रन (1,322 टेस्ट, 1,202 वनडे, 211 टी 20)
3. कुल औसत: 68.37
4. कितनी सेंचुरी, कितनी फिफ्टी: 11 सेंचुरी (5 टेस्ट, 6 वनडे), 9 फिफ्टी

क्या है

1. आईसीसी ने विराट कोहली को साल 2018 की परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी दोनों टेस्ट और वनडे टीम का **कप्तान** भी चुना है।
2. विराट के अलावा टीम इंडिया के तेज गेंदबाज **जसप्रीत** बुमराह को आईसीसी की इन दोनों टीमों में जगह मिली है। इसके अलावा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
3. वहीं वनडे टीम में विराट और बुमराह के अलावा भारत से ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और चाइनामैन बोलर कुलदीप यादव को भी चुना गया है।
4. ICC ने बयान जारी कर कहा, कोहली प्ले के इन तीनों प्रमुख पुरस्कारों को एक साथ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ ही उन्हें आईसीसी टेस्ट और वनडे टीमों का कप्तान भी घोषित किया गया है।

आईसीएआर की 'किसान गांधी' ने पहला पुरस्कार जीता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की गणतंत्र दिवस परेड - 2019 में प्रस्तुत झांकी 'किसान गांधी' को **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण ने नई दिल्ली में आईसीएआर की टीम को पुरस्कार प्रदान किया। आईसीएआर की झांकी में डेयरी फार्मिंग के महत्व, देसी नस्लों का इस्तेमाल और ग्रामीण समृद्धि के लिए पशुधन आधारित **जैविक कृषि** दिखाई गई। आईसीएआर की झांकी 'किसान गांधी' में ग्रामीण समुदाय की समृद्धि के लिए कृषि और पशुधन सुधारने के गांधी जी के विजन को दिखाया गया।

क्या है

1. गांधी जी **1927 में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र**, बेंगलुरु में डेयरी फार्मिंग पर 15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने 1935 में इंदौर में पौध उद्योग संस्थान में खाद तैयार करने की 'इंदौर पद्धति' की सराहना की थी।

2. गांधीवादी दर्शन में स्वदेशी नस्लों, जैविक कृषि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बकरी के दूध को प्रोत्साहन शामिल है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथक रूप से भारतीय कृषि को बदलने की दिशा में काम कर रही है ताकि पशुधन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अन्नदाता किसानों की आय बढ़ सके।

3. भारत ने अत्याधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी का विकास और उपयोग करके खाद्य आत्मनिर्भरता में सफलता प्राप्त की है और भारत विश्व में दूध और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है।

4. झांकी में बापू को बकरी और गाय के साथ दिखाया गया है। झांकी में जैविक कृषि, कपास

तथा दुग्ध उत्पादन में क्रांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा विश्लेषण को दिखाया गया है।

फ्लैशबैक

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है।
2. रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है।

5. कस्तूरबा गांधी को चरखा चलाते हुए और वर्धा आश्रम की बापू कुटी में पशुओं की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। यह आजीविका आधारित सतत और जलवायु परिवर्तनरोधी कृषि का संकेत देती है।
6. 70वें गणतंत्र दिवस परेड में 22 झाकियां थीं जिनमें से 16 झाकी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की और 6 झाकियां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की थीं।
7. आईसीएआर गणतंत्र दिवस झाकी-2018 का विषय मिश्रित खेती, खुशियों की खेती था।

शीर्ष ग्लोबल थिंकर्स में मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर **मुकेश अंबानी** ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 2019 की वार्षिक सूची में जगह बनाई है। उन्हें टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल किया गया है। मैगजीन के अनुसार भारत में इंटरनेट क्रांति को आगे बढ़ाने में अंबानी की अहम भूमिका रही है।

क्या है

1. अंबानी ने पिछले साल चीन के उद्योगपति **जैक मा** को पीछे छोड़कर सबसे अमीर एशियाई का तमगा हासिल किया था। उस समय उनकी संपत्ति 44.3 अरब डॉलर थी।
2. मैगजीन का कहना है कि जैसे को अंबानी ने ऑयल, गैस और रिटेल सेक्टर से संपदा बनाई है लेकिन उनकी रिलायंस जियो ने देश में सबसे ज्यादा असर डाला है।
3. शुरू में डाटा और वॉयस सेवाएं मुफ्त देने से जियो ने आसानी से दस करोड़ ग्राहक जुटा लिए।

पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस

न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा ने 18 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के 26वें **चीफ जस्टिस** के तौर पर शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादे तरीके से यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया जिसमें भारत समेत विदेशों के कई पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नये **प्रधान न्यायाधीश** को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खोसा ने प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद संभाला है।

क्या है

1. तुर्की, दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया।
2. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान में 1954 में जन्मे न्यायमूर्ति खोसा ने पंजाब विश्वविद्यालय और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की।
3. वह उस तीन सदस्यीय पीठ का हिस्सा रहे हैं जिसने ईशानिदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी किया था।
4. साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्रियों यूसुफ रजा गिलानी एवं नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने वाली पीठों का भी हिस्सा रह चुके हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए महानिदेशक

वरिष्ठ आइपीएस प्रभात सिंह को **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (एनएचआरसी) का महानिदेशक (अन्वेषण) नियुक्त किया गया। वह फिलहाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिंह की नियुक्ति 30 अप्रैल 2020 तक के लिए की गई है। कार्मिक मंत्रालय ने एक अन्य आदेश में कहा कि एसएन प्रधान को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का महानिदेशक बनाया गया है। प्रधान 1988 बैच के झारखंड कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं। वह फिलहाल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

क्या है

1. **भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।

2. इसकी स्थापना **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993** के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यह सविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है।
3. यह एक बहु सदस्य निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।

आधार कार्ड दिखाकर नेपाल और भूटान की यात्रा

भारत के 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के नागरिक नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए **आधार कार्ड** को वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इन दोनों वर्गों के अलावा अन्य भारतीय दोनों पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए आधार कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। दोनों देशों की **यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं** होती है। भारतीय नागरिकों के पास यदि वैध पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र है तो उन्हें नेपाल और भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है।

क्या है

1. इससे पहले इन दोनों देशों की यात्रा के लिए 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) कार्ड या राशन कार्ड दिखाना पड़ता था, लेकिन ये लोग **आधार कार्ड का इस्तेमाल** नहीं कर सकते थे।
2. आधार कार्ड को अब इस सूची में जोड़ दिया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भारत और नेपाल के बीच यात्रा के लिए स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।
3. हालांकि नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र भारत वापसी की केवल एक यात्रा के लिए मान्य होगा।
4. 15 से 18 साल के किशोरों को उनके स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के पास छह महीने की न्यूनतम वैधता के साथ या तो भारतीय पासपोर्ट या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
5. भारतीय नागरिकों के पास यदि वैध पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र है तो उन्हें नेपाल और भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है।

प्रथम शेख सौद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात वैज्ञानिक सीएनआर राव को प्रथम शेख सौद **अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार** के लिए चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मैटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मैटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाएगा।

क्या है

1. **जवाहरलाल नेहरू** सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) ने यहां एक बयान में बताया, श्रुस्कार के लिए प्रो राव का चयन कमेटी ने सर्वसम्मति से किया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, मेडल और एक लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 71 लाख रुपये) दिए जाएंगे।
2. प्रो राव को यह अवार्ड 25 फरवरी को यूएई के रास अल खैमा में एडवांस मैटेरियल्स पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में दिया जाएगा। वहां के शासक शेख सौद खुद राव को यह पुरस्कार देंगे।
3. प्रो राव नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, लाइनस पॉलिंग रिसर्च प्रोफेसर और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के मानद अध्यक्ष हैं। उन्हें वर्ष 2014 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था।

दूसरा ऑयल डिमांड सेंटर बन जाएगा भारत

वर्ष 2019 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल डिमांड ग्रोथ सेंटर बन जाएगा। ऐसा ऑटो ईंधन और एलपीजी की खपत के चलते देखने को मिलेगा। यह अनुमान रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने लगाया है। अपनी रिपोर्ट में वुड मैकेंजी ने बताया कि **नोटबंदी** और **जीएसटी** (वस्तु एवं सेवा कर) के कार्यान्वयन के असर से उबरने के बाद वर्ष 2018 में भारत की ऑयल डिमांड ग्रोथ में सुधार देखने को मिला है। ग्लोबल डिमांड ग्रोथ में इसका योगदान 14 फीसद का है, या 2,45,000 बैरल प्रति दिन का।

क्या है

1. इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, जून 2019 में समान स्तर पर तेल की मांग बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं।
2. इसके परिणामस्वरूप भारत 2019 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऑयल डिमांड सेंटर (मांग वृद्धि केंद्र) बन जाएगा। नंबर एक पर अमेरिका होगा लेकिन भारत चीन से आगे होगा।
3. परिवहन ईंधन गैसोलीन और डीजल एवं आवासीय एलपीजी तेल की मांग में वृद्धि के दो मुख्य चालक बने रहेंगे।
4. यूएस एनर्जी इन्फार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) के मुताबिक भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन से पीछे है और वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।
5. इसने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 206.2 मिलियन टन तेल का उपभोग किया था। अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपभोग 157.4 मिलियन टन रहा था जो कि बीते वर्ष की अवधि के मुकाबले 2.5 फीसद ज्यादा है।

अंतर्धार्मिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि **हिंदू महिला** की मुस्लिम पुरुष के साथ शादी अनियमित या वैध नहीं है, लेकिन ऐसे विवाह से जन्मी संतान वैध है। यह संतान पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार मानी जाएगी। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एमएम शांतनगौडर की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को कायम रखा, जिसमें उसने मोहम्मद इलियास व वल्लिअम्मा (जो शादी के वक्त हिंदू थी) **दंपती के बेटे को वैध** मानते हुए पिता की संपत्ति में हिस्सेदार माना था।

क्या है

1. सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले में निष्कर्ष रूप में कहा, एक मुस्लिम पुरुष की किसी मूर्तिपूजक या अग्नि की उपासक महिला से शादी न तो वैध है और न ही शून्य, बल्कि वह सिर्फ अनियमित विवाह है। ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा पिता की संपत्ति में हिस्से का हकदार है।
2. शीर्ष कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, जिसमें प्रतिमा या तस्वीर शामिल है, उन पर पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें सजाते हैं। ऐसे में किसी हिंदू महिला का मुस्लिम से निकाह अनियमित माना जाएगा।
3. ऐसी अनियमित शादी का कानूनी प्रभाव यह होगा कि रिश्ता टूटने की दशा में पत्नी मेहर की राशि पाने की तो हकदार होगी लेकिन वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकेगी। वहीं इस दंपति से जन्मा बच्चा अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का पात्र होगा।
4. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दूसरी ओर शादी शून्य घोषित होने का मतलब है कि दोनों पक्षों और संतान को किसी संपत्ति के अधिकार नहीं होंगे।

यह था मामला

1. इलियास और वल्लिअम्मा के बेटे शम्सुद्दीन ने अपने पिता की मौत के बाद विरासत में मिली पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी पर दावा किया था।
2. केरल हाई कोर्ट ने उसके दावे को सही माना था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
3. अपील खारिज करते हुए शीर्ष कोर्ट ने ऐसी शादी से जन्म बच्चे को पिता की पैतृक संपत्ति में हकदार माना है।

कृष्णा सोबती का निधन

हिंदी साहित्य की जानी मानी हस्ताक्षर और प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। 18 फरवरी 1924 को गुजरात (वर्तमान पाकिस्तान) में जन्मी सोबती साहसपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती थीं। बतौर लेखिका 1950 में कहानी 'लामा' से साहित्यिक यात्रा शुरू करने वाली कृष्णा सोबती स्त्री की आजादी और न्याय की पक्षधर थी और यह उनके उपन्यासों में भी दिखा। 'जिंदगीनामा' के लिए 1980 में सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया जो कि अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम को निगम बोध घाट पर विद्युत शव दाह गृह में होगा।

क्या है

1. कृष्णा सोबती को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2017 में मिला था।
2. इसके अलावा, कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास 'जिंदगीनामा' के लिए साल 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें 1996 में अकादमी के उच्चतम सम्मान 'साहित्य अकादमी फेलोशिप' से नवाजा गया था। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्मभूषण, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।
3. कृष्णा सोबती के कालजयी उपन्यासों में 'सूरजमुखी अंधेरे के', 'दिलोदानिश', 'जिंदगीनामा', 'ऐ लड़की', 'समय सरगम', 'मित्रो मरजानी', 'जैनी मेहरबान सिंह', 'हम हशमत', 'बादलों के घेरे' शामिल हैं। लेखिका की इन कृतियों ने साहित्य को समृद्ध किया है।
4. चर्चित लेखिका के निधन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया है- शकई पीढ़ियों को अपनी दमदार लेखनी से प्रभावित करने वाली कथाकार कृष्णा सोबती जी का चला जाना गहरा शोक पैदा करता है। उनका लिखा और उनका संघर्ष हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्रद्धांजलि।
5. पिछले कई दशक से अपनी लेखनी से पाठकों अध्ययन की भूख को शांत कर रहीं लेखिका कृष्णा सोबती का 'बुद्ध का कमंडल लद्दाख' और 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान' भी उनके लेखन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

वीरता पदक से पुलिसकर्मी सम्मानित

Republic Day 2019, गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के कुल 855 कर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें से 149 कर्मियों को जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और अन्य क्षेत्रों में बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया। जबकि देश के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल-सीआरपीएफ को बहादुरी के लिए सबसे ज्यादा 44 पुरस्कार मिले।

क्या है

1. ओडिशा पुलिस को 26 पदक और जम्मू-कश्मीर पुलिस को 25 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस को 14 पदकों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी बल्थ के तीन जवानों को मरणोपरांत शीर्ष सम्मान - राष्ट्रपति के पुलिस पदक (पीपीएमजी) से पुरस्कृत किया गया।
2. वीरता पदक के अन्य विजेताओं में मेघालय पुलिस के 13, उत्तर प्रदेश पुलिस के 10, सीमा सुरक्षा बल के आठ, दिल्ली पुलिस के चार, झारखंड पुलिस के तीन और असम राइफल्स एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के एक-एक कर्मी शामिल थे।
3. गृह मंत्रालय के एक आदेश में बताया गया कि विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय पुलिस बलों एवं संगठनों के महिला एवं पुरुष कर्मियों को कुल 146 पुलिस वीरता पदकों, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के 74 पुलिस पदकों और सहायनीय सेवा के लिए 632 पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया।

नेपाल के क्रिकेटर ने तोड़ा सचिन का रेकॉर्ड

नेपाल के रोहित पाउडेल ने इंटरनैशनल क्रिकेट (पुरुषों) में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी बनाने का रेकॉर्ड बना दिया है। 16 साल 146 दिन की आयु में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 55 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने शॉर्ट ऑफ क्रिकेट्स भारतीय दिग्गज सचिन तेंडुलकर का 29 साल पुराना रेकॉर्ड भी तोड़ दिया। पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय हाफ सेंचुरी लगाने की बात करें तो यह रेकॉर्ड सचिन तेंडुलकर के नाम था जिन्होंने 16 साल और 213 दिनों की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 59 रनों की पारी खेली थी। यह मैच 23 नवंबर 1989 से पाकिस्तान के फैसलाबाद में खेला गया था।

क्या है

1. नेपाल के रोहित ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के वनडे इंटरनैशनल में सबसे युवा हाफ सेंचुरियन का रेकॉर्ड को भी तोड़ा। अफरीदी ने करीब 23 साल पहले 16 साल 217 की उम्र में वनडे इंटरनैशनल में 50 का आंकड़ा पार किया था। उन्होंने उस मैच में 102 रनों की पारी खेली थी।
2. 1996 में नैरोबी में श्री लंका के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने महज 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया था।
3. सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पाउडेल ने 58 गेंदों पर 55 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके लगाए। उनकी पारी की बदौलत नेपाल ने 50 ओवरों में 9 विकेट पर 242 रन बनाए थे। जवाब में मेजबान यूएई की पूरी टीम 97 रनों पर ऑल आउट हो गई और नेपाल ने 145 रनों से जीत हासिल की। इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। यूएई ने पहला मैच जीता था।
4. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी बनाने का रेकॉर्ड साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर जोहमरी लॉगटेनबर्ग के नाम है जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में अर्धशतक लगाया।
5. पाउडेल की बात करें तो अंडर-19 एशिया कप में कमलेश नगरकोटी के एक ओवर में 24 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं। 2002 में जन्में पाउडेल ने अगस्त 2018 में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। नेपाल को मई 2018 में उस समय व्क टीम का दर्जा मिला था जब उसने हारे में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में पपुआ न्यू गिनी को हराया था।

गणतंत्र दिवस पर भारत ने नेपाल को दी उपहार

भारत ने 26 जनवरी 2019 को नेपाल को अपना सहयोग बढ़ाते विस्तृत करते हुए 30 एम्बुलेंस और छह बसों का उपहार दिया। भारत ने हिमालयी देश को यह उपहार 70वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास परिसर में आयोजित समारोह में नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने एम्बुलेंसों और बसों की चाभी संगठनों को सौंपी।

क्या है

1. भारत सरकार 1994 से नेपाल में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सेवाओं में पहुंच का विस्तार करने के लिए पूरे नेपाल में विभिन्न संगठनों को 722 एम्बुलेंस और 142 बसें दे चुकी है।
2. राजदूत पुरी ने गोरखा रेजिमेंट के युद्ध में शामिल हुए पूर्व सैनिकों के परिजनों को नकदी और पूरे देश के 53 स्कूलों एवं पुस्तकालयों को पुस्तकें उपहार में दीं।
3. पुरी ने भारतीय ध्वज फहराया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम भारत के राष्ट्रपति का संदेश पढ़ कर सुनाया। इस कार्यक्रम में 2,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

‘नारी शक्ति’ को मिली नई पहचान

Oxford Dictionary Word of the year, ‘नारी शक्ति’ (Nari Shakati) को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी (Oxford Dictionary) ने एक नई पहचान दी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदी के चर्चित शब्द नारी शक्ति को साल 2018 का **हिन्दी शब्द** चुना गया है। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव में को नारी शक्ति को 2018 का हिंदी शब्द घोषित किया है। पैनल डिस्कशन में लंबी चर्चा के बाद इस शब्द को डिक्शनरी ऑफ 2018 में शामिल कर लिया गया है।

क्या है

1. ऑक्सफोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया, शसाल का हिंदी शब्द नारी शक्ति, एक शब्द या भाव है, जिसने काफी ध्यान खींचा है। यह पिछले साल की प्रकृति, मिजाज और विचारमग्नता को जाहिर करता है।
2. बयान के मुताबिक, ‘आज इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालने के लिए किया जाता है।’ भारत में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की टीम ने साल के **हिंदी शब्द का चुनाव** किया। इसमें भाषा विशेषज्ञों की अडवायजरी टीम ने मदद की जिसमें अशोक कुमार शर्मा, कार्तिका अग्रवाल और नमिता गोखले शामिल थे।
3. नारी का मतलब होता है महिला और पावर का मतलब होता है शक्ति। इस शब्द का पूरा मतलब होता है—महिला आज अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रही हैं।
4. नारी शक्ति शब्द को इन कुछ सालों में इसलिए ज्यादा महत्व मिला क्योंकि केंद्र सरकार ने महिलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा विकास प्रक्रिया में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को देखा गया।
5. गौरतलब है कि इस शब्द का चयन ऐसे समय पर हुआ है, जब देश 70वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर होने वाली कई महत्वपूर्ण परेडों का नेतृत्व महिलाओं ने किया। जो नारी शक्ति का उदाहरण हैं। ऑक्सफोर्ड ने साल 2017 का हिंदी शब्द **आधार** को चुना था।

पूनम खेत्रपाल फिर बनीं डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक

पूनम खेत्रपाल सिंह को दोबारा पांच और वर्षों के लिए विश्व **स्वास्थ्य संगठन** (डब्ल्यूएचओ) का क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व एशिया) नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से खेत्रपाल सिंह का समर्थन किया। उन्हें क्षेत्र के 11 **सदस्य देशों** ने और पांच वर्षों के लिए सर्वसम्मति से नामित किया।

क्या है

1. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टीए घेब्रेयेसस ने कहा, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक खेत्रपाल सिंह ने क्षेत्र को बेहतरीन नेतृत्व प्रदान किया।
2. यह क्षेत्र दुनिया की चौथाई आबादी का **प्रतिनिधित्व** करता है, जहां रोगों का असंतुलित भार भी है। खेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
3. खेत्रपाल सिंह ने कहा, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में फिर एक बार नियुक्त किया

पल्लेशबैक

1. दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया एशिया का एक उपभाग है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि से चीन के दक्षिण, भारत के पूर्व, न्यू गिनी के पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के देश आते हैं।
2. यह क्षेत्र भूगर्भीय प्लेटों के चौराहे पर स्थित है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में भारी भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं।
3. दक्षिण पूर्व एशिया को दो भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है: मुख्यभूमि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे इंडोचायना भी कहते हैं, के अन्दर कंबोडिया, लाओस, बर्मा (म्यांमार), थाईलैंड, वियतनाम और प्रायद्वीपीय मलेशिया आते हैं और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें ब्रुनेई, पूर्व मलेशिया, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, क्रिसमस द्वीप और सिंगापुर शामिल हैं।

जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

4. खेत्रपाल सिंह का दूसरा कार्यकाल एक फरवरी से शुरू हो रहा है।

सरदार सरोवर बांध से जल दिलवाने की मांग वाली याचिका खारिज

सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी की डाउन स्ट्रीम में पर्याप्त मात्रा में पानी दिए जाने की मांग वाली याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने खारिज कर दी है। एनजीटी ने कहा है कि यह मामला पहले से ही एक ट्रिब्यूनल के पास है, वह इस पर विचार कर रहा है। इसलिए इस तरह की मांग वाली याचिका की सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या है

1. जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, **जल विवाद पंचाट** और नर्मदा नियंत्रण अधिकरण मामले को देख रहे हैं।
2. यह विवाद को सुलझाने का उचित तरीका है। इसलिए इस पर विश्वास करना चाहिए और याचिकाकर्ता अपनी अपेक्षा ट्रिब्यूनल के सामने रखनी चाहिए।
3. एनजीटी ने यह बात **नर्मदा प्रदूषण निवारण समिति** और भरूच नागरिक परिषद की याचिकाओं पर विचार करते हुए कही। इन याचिकाओं में सरदार सरोवर से नर्मदा की डाउन स्ट्रीम में प्रतिदिन 1,500 क्यूसेक पानी डलवाने का आदेश देने की मांग की गई थी।

फ्लैशबैक

1. सरदार सरोवर दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊँचा (नींव सहित 163 मीटर) है।
2. नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है।
3. इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफी ऊपर चली गई हैं।

दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अब भी **दुनिया का सबसे व्यस्त** हवाई अड्डा बना हुआ है। हवाई अड्डे की ओर से बताया गया कि उसने 2018 में 8.9 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया। वर्ष 2017 में यहां आने वाले यात्रियों की संख्या 8.8 करोड़ थी। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पहली बार 2014 में अंतरराष्ट्रीय यातायात में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के तौर पर लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे को **पीछे छोड़** दिया था।

क्या है

1. दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सबसे अपनी इस उपलब्धि को बरकरार रखा है और यहां से करीब 75 एयरलाइंस अपनी उड़ानों को संचालित करती हैं। जॉर्जिया में हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल मिलाकर दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना हुआ है।
2. नए आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में कुल 89,149,387 यात्रियों ने हवाई अड्डे का उपयोग किया। भारत हवाई अड्डे के लिए यातायात का **सबसे बड़ा स्रोत** रहा। भारत के मुंबई, दिल्ली और कोचीन जैसे शहरों से ज्यादातर यात्रियों ने सफर किया।
3. सउदी युनाइटेड किंगडम के यात्रियों को पछाड़कर 6.4 मिलियन से अधिक यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर है।
4. लगभग 6.3 मिलियन ब्रिटिश नागरिकों ने हवाई अड्डे का उपयोग किया। इन देशों के अलावा, चीन से 3.5 मिलियन यात्री, अमेरिका से 3.2 मिलियन और रूस से लगभग 1.5 मिलियन यात्रियों ने दुबई हवाई अड्डे का उपयोग किया। दुबई हवाई अड्डे ने पिछले साल जुलाई में दो बार 8 मिलियन यात्रियों का आंकड़ा पार किया।

भोपाल गैस कांड संबंधी मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट भोपाल गैस कांड से संबंधित एक मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सरकार ने 1984 के गैस पीड़ितों को अधिक मुआवजा दिलाने के लिए अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, अब डॉव केमिकल्स, से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह केंद्र की सुधारात्मक याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगी। कंपनी ने पहले पीड़ितों के लिए मुआवजा के तौर पर 715 करोड़ रुपये दिए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे के लिए अतिरिक्त धन के लिए कंपनियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

क्या है

1. वर्ष 1984 में दो और तीन दिसंबर की रात को कंपनी के भोपाल प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट (मिक) गैस का रिसाव हुआ था। इसमें तीन हजार लोगों की मौत हुई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे।
2. पीड़ित उचित मुआवजा और बेहतर इलाज के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने कंपनी से अधिक मुआवजे के लिए 2010 में सुधारात्मक याचिका दायर की थी।
3. पीड़ित भी सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने हस्ताक्षर के साथ याचिका भेजने की तैयारी में थे। मध्य प्रदेश के भोपाल गैस कांड राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास नारंग ने भी कहा था कि पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिला है।
4. जून, 2010 में भोपाल की एक अदालत ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सात अधिकारियों को दो-दो साल कैद की सुनाई थी।
5. इस मामले में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन वारेन एंडरसन मुख्य आरोपी था, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं जा सका। फरवरी, 1992 में भोपाल की सीजेएम कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। अदालत से उसके खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। सितंबर, 2014 में उसकी मौत हो गई थी।